[Shri Asoka Mehta]

this case I thought the House knew as to why I had resigned.

AN HON. MEMBER : Everybody knew.

SHRI ASOKA MEHTA : I did not want to take the time of the House and to waste it. I am sure, everybody knows here that a certain proposition was there before us for voting and it was not possible for me to vote down that proposition. I do not want to make any further statement to that.

12.28 HRS.

BIHAR BUDGET, 1968-69—*contd.*

GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

MR. SPEAKER : We have already taken 2 hours in discussing the Bihar budget. 3 hours were allotted. Our UP friends were complaining that whereas Bihar has been given 3 hours, UP, which is double the size of Bihar, has been given only 1 hour. They want that UP should be given some more time.

For the Bihar budget, only one hour remains and there are a large number of members desiring to speak from all parties. May I appeal to them to be brief ? We must complete it in one hour. After one hour, I am going to put it to vote. There should be some end somewhere. I cannot enable all the Members to speak; it is not within my power. So within one hour I am going to close it because only one hour more is there. Shri Mudrika Sinha may resume his speech.

श्री मुद्रिका सिंह (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बिहार की रत्न गर्भा और शस्य श्यामला भूमि होने के बावजूद वहां के लोग निर्धन हैं और इस निर्धनता के तीन मुख्य कारण हैं। एक कारण तो स्वतः उस राज्य की गरीबी है। उस गरीबी के कारण इच्छा होने पर भी विकास कार्यों के लिए राजस्व को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर करों का बोझ बढ़ाया जाए तो किसानों की तथा दूसरे लोगों की क्रय शक्ति और दातव्य शक्ति घटेगी और खेती के उत्थान के लिए जो उन्हें पूंजी का निर्माण करना चाहिये, उसको वे नहीं कर सकेंगे। फलतः गरीबी और बढ़ती जाएगी।

दूसरा कारण है हमारे राज्य का बाहरी लोगों से शोषण।

शिर्फ छोटा नागपुर में कोयला, अभ्रक मैंगनीज, बाक्साइट, सीमेंट और आयरन ओर आदि की हज़ारों खदानें हैं, लेकिन आप को जान कर आश्चर्य होगा कि इन हज़ारों खदानों में से एक खदान के भी मालिक बिहारी नहीं हैं; सभी बाहर के लोग हैं। फलतः उन खदानों से जो मुनाफ़ा होता है, वह भी हमारे राज्य से बाहर चला जाता है। चूंकि उन मालिकों का हैड आफ़िस कलकत्ता में है, इस लिए उन के आय-कर का एसेसमेंट वहां ही होता है; उस का समुचित हिसाब हमें नहीं मिलता है और आयकर का बहुत बड़ा हिस्सा बंगाल को मिल जाता है; हम उस से वंचित रह जाते हैं। इसी तरह दर्जनों चीनी के कारखाने हैं पर एक भी कारखाने के मालिक बिहारी नहीं है।

12.31 HRS.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

हम लोगों को इनमें नौकरियां पाने की उम्मीद थी लेकिन देखा जाता है कि जितनी की जगहें, हैं, उन पर वे लोग अपने राज्य के आदमी, अपने सगे सम्बन्धी, अपने भाई भगिना भतीजे रखते हैं। इन दिनों एक नई बीमारी शुरू हो गई है। पहले कम से कम चपरासी, ड्राइवर और आफ़िस बाय के पदों पर बिहार के लोग बहाल होते थे। लेकिन

अब यह देखा जाता है कि इन छोटी छोटी जगहों पर भी बाहर के लोग बहाल किये जा रहे हैं। इस का फल यह हो रहा है कि रत्नगर्भ वसुन्धरा में हजारों खदानों होने और कारखानों के बावजूद न हम उन के प्राफ़िट से लाभ उठा पा रहे हैं, न हम आयकर का हिस्सा ले पा रहे हैं और न ही हमें नौकरियां ही मिल पा रही हैं, जिस से बेकारी का सवाल हल हो सके। यह प्रवृत्ति सिर्फ प्राईवेट फ़र्मों में ही नहीं है, केन्द्रीय सरकार की गगन-चुम्बी फ़ैक्टरियों में भी है, चाहे वह हटिया हो, माराफरी में बोकारो की नई स्टील फैक्टरी हो, सिन्दरी हो, गुमिया की एक्सप्लासिव्ज फ़ैक्टरी हो या बरौनी की फ़ैक्टरी हो। सभी जगहों पर जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर या जेनेरल मैनेजर आ रहे हैं, वे अपने साथ अपने सगे सम्बन्धी भाई भगिना भतीजों की एक फ़ौज ला रहे हैं। वे ऊंची नौकरियों को बाहर के लोगों से तो भर ही रहे हैं, चपरासी और पानी देने वाले लड़के भी बाहर से ला कर बहाल किये जा रहे हैं। इस तरह हमारे प्रान्त को कोई लाभ नहीं होता है।

माननीय सदस्य, श्री मधोक, ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अब तक क्या किया। जब बाहर के लोग जा कर इस निर्धन प्रान्त का शोषण करें, मुनाफ़ा अपने राज्यों में ले जायें, हैड आफ़िस कलकत्ता में रखें, जिस से आयकर का भी हिस्सा हमें न मिले, नौकरियों से भी हम महरुम रखे जायें, तो उस प्रान्त की दयनीय स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है और किस तरह उस का विकास किया जा सकता है?

केन्द्रीय सरकार की ओर से हमारे राज्य के साथ बराबर बिमाता का सा व्यवहार हुआ है, स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट हुआ है। हर एक क्षेत्र में यही स्थिति है। बिहार नदियों का प्रान्त है। लेकिन इन नदियों को आज तक पालतू नहीं किया जा सका। अगर केन्द्रीय सरकार कोसी की वैस्ट कैनाल और गंडक योजना को पूर्ण कर पाती, हमारे क्षेत्र, गया ज़िले, की, जो हमेशा अकाल के कगार पर खड़ा रहता है, कोयल परियोजना को अगर पूरा किया जाता, जिस पर 13 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं, तो अकाल में जो लाखों करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, वे बच जाते, हमारे यहां तीन फसलें होतीं, हम एक डेफ़िसिट प्रान्त के स्थान पर सरप्लस प्रान्त बन जाते और ज्यादा से ज्यादा अन्न उत्पन्न कर के केरल जैसे प्रान्त को लाखों टन चावल दे पाते, जिस का प्रश्न हमारे खाद्य मंत्री के लिए एक हैडेक बना हुआ है। काश, नदियों को पालतू बनाया जाता। काश, हमारे यहां सिंचाई योजनायें चलाई जातीं। कास, मातृभूमि की कोख में जो अनवरत जल राशि है, डीप बोरिंग के जरिये उस पानी को ऊपर ला कर सिंचाई का इन्तज़ाम किया जाता तो हमारा राज्य भी सुखी सम्पन्न और धनी राज्य रहता। लेकिन यह सब नही हो पाया।

उम्मीद थी कि डी. वी. सी. से हमें लाभ होगा। लेकिन हुआ क्या? हमारी भूमि जलमग्न हुई, हमारे गांव डूबे, हमारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए, जिन को बसाने का सवाल पैदा हुआ। लेकिन उस योजना से बाढ़ नियंत्रण का लाभ बंगाल को हुआ, सिंचाई का लाभ बंगाल को हुआ। हमें बिजली की उम्मीद थी, लेकिन हम ट्रेन्समिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अभाव में उस से भी महरूम रह गये, केन्द्रीय सरकार के अन्यायपूर्ण व्यवहार की वजह से हम उस से भी लाभ नहीं उठा सके।

[श्री भुद्रिका सिंह]

एक बिजली को ही आप देखें कि किस तरह हमारे साथ स्टेपमदरली ट्रीटमेंट हुआ है। 1962 से 1968 तक हमारे राज्य को केन्द्र से 17 करोड़ रुपया मिला, जब कि मद्रास को 35 करोड़ रुपया मिला। हमारे बिहार में कुल 67,765 गांव हैं, लेकिन केवल 6,375 गांवों का इलैक्ट्रिफ़िकेशन हुआ है, जब कि मद्रास में सिर्फ़ 14,124 गांव हैं, जिन में से 8,018 गांवों का इलैक्ट्रिफ़िकेशन हो चुका है।

जहां तक ट्रांसमिशन लाइन्ज़ का सम्बन्ध है, बिहार में एक लाख की आबादी पर 92 मील ट्रांसमिशन लाइन है, जब कि मद्रास में एक लाख की आबादी पर 208 मील ट्रांसमिशन लाइन है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्ज़ की भी यही हालत है। बिहार में 100 स्क्वेयर माइल्ज़ में 62 मील डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जब कि मद्रास में 100 स्क्वेयर माइल्ज़ में 139 मील डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है।

इसी तरह से मद्रास, आन्ध्र, मैसूर, महाराष्ट्र और पंजाब, सब की तुलना में आज बिहार पीछे है। अभी हमारा जो बजट आया है, उस में भी कटौती की गई है। हमारे ऊपर अगर किसी की विशेष कृपा है, तो वह चव्हाण साहब की है। हमें नदी के किनारे के वृक्ष की तरह बूढ़े गवर्नर दिये गये। जिस किसी प्रान्त में राष्ट्रपति शासन हुआ, तो कहीं एड़वाइज़र नहीं दिये गये, लेकिन उन्हें न जाने क्यों हम पर इतनी दया आ गई कि हमें दो एडवाइज़र भी दे दिये गये। उन में से एक एडवाइज़र अंधे हैं। गवर्नर ऐसे हैं कि कच्ची सड़क पर मोटर में पांच, छः मील भी नहीं चल सकते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन क्या कर रहा है?

ये दोनों एडवाइज़र, श्री राव और श्री आनन्द, जब वहां गये, तो दोनों में होड़ हुई किस के पास अधिक अच्छा बंगला हो और किस के पास अधिक अच्छा फ़रनीचर हो। पुराना फ़रनीचर हटाया गया और कलकत्ता से नया-फ़रनीचर लाया गया। वे लोग पगले मुहम्मद तुग़लक की तरह काम कर रहे हैं— अफ़सरों को दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली लाया जा रहा है। वहां पर कोई भी रचनात्मक काम नहीं हो रहा है।

अगर हमारे कृषि-प्रधान राज्य में एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बना देते, हमारे यहां की हज़ारों हज़ार एकड़ बंजट परती ज़मीन को रीक्लेम कर के उस में फ़ार्म बना कर बीज पैदा करते, तो हमारे राज्य को कुछ लाभ होता। पूर्णिया में हज़ारों एकड़ ऐसी ज़मीन है, जहां सिंचाई का प्रबन्ध हो गया है, लेकिन उस को रीक्लेम कर के, वहा फ़ार्म बना कर, बीज पैदा नहीं किया जा रहा है। अगर इस प्रकार के काम किये जायें, तो हमारा राज्य समृद्धिशाली हो सकता है। केन्द्रीय सरकार ने आज तक हमारे साथ जो स्टेपमदरली ट्रीटमेंट किया है, उस लास को उसे कामपेन्सेट करना चाहिए। जब तक वह ऐसा नहीं करेगी, हमारा राज्य प्रगति नहीं कर सकता है।

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का बजट जिस रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया गया, है वह नई बोतल में पुरानी शराब के समान है। इस में कोई प्रगतिशील या क्रान्तिकारी कदम उठाने की बात तो कतई नहीं है। मैं समझता हूं कि आज की बदलती हुई दुनिया में एक पिछड़े हुए राज्य के लिए जैसा क्रान्तिकारी बजट चाहिए, ठीक उस के विपरीत यह बजट है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 20 वर्षों से बिहार में कांग्रेस का शासन रहा है और

बिहार राज्य में जिस प्रकार प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ हैं, बेशुमार नदियों में पानी है, मेहनत कश इन्सान हैं, इस तरह की सारी चीजों के रहने के बावजूद भी बिहार भूखा और बेकार है, यह आश्चर्य और ताज्जुब की बात है। बिहार के सामने जो आज संकटपूर्ण स्थिति है जिस तरह बिहार की आबादी पिछले 30 वर्षों में तेजी के साथ बढ़ी है, 1 करोड़ 50 लाख आबादी पिछले 30 वर्षों में बढ़ी है और 1901 से लेकर 1968 तक इतने आदमी वहां बढ़े हैं कि जितनी आबादी पहले थी उस से दुगुनी आज बिहार की आबादी हो गई है लेकिन जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी है उस रफ्तार से बिहार के लोगों को या तो कृषि में या उद्योग में लगाने की व्यवस्था नहीं हो सकी है जिस की वजह से वहां एक विस्फोटक स्थिति है। लोग बेकार हैं। बेकारी के आलम में वहां पर प्रशासन की तरफ से जो दमन चक्र चल रहा है उस की वजह से बिहार में एक अजीबो-गरीब हालत है, चारों तरफ अराजकता है। लोग रोज़ी नहीं पा रहे हैं, भर पेट भोजन नहीं पा रहे हैं जब कि बिहार में, सम्पूर्ण देश में प्राप्त खनिज पदार्थों का जितना वजन है उस का 43.3 प्रतिशत और उन का जितना मूल्य होगा उस का 30.6 प्रतिशत बिहार में पाया जाता है। भारत में पाये जाने वाले कोयले का 54 प्रतिशत, लोहे का 48.28 प्रतिशत, तांबे का शत प्रतिशत और अभ्रक का 60.34 प्रतिशत बिहार में पाया जाता है। इसी प्रकार भारत में पाये जाने वाले लौह का 65 प्रतिशत बिहारों में पाया जाता है। फिर भी भारी और लघु उद्योग के मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है। जमशेदपुर, टाटा, सिन्दरी, हटिया आदि में जो भी उद्योग हैं उन में बिहार के लोगों की भर्ती होनी चाहिए परन्तु ठीक उस के विपरीत वहां की जा रही है। इस सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। अभी अभी बोकारो स्टील के नाम से एक बहुत बड़ा औद्योगीकरण वहां होने जा रहा है जहां हजारों हजार लोग काम में लगेंगे, लेकिन उस जगह पर आज इस तरह की धांधली वहां के अधिकारी कर रहे हैं कि जो वहां के आदिवासी और वाशिंदे हैं जिन की जमीन ले ली गई है, जिन के गांव उजाड़ दिए गए हैं, उन लोगों को उस में भर्ती न कर के बाहर के लोगों को भर्ती किया जा रहा है और इन्हें भूखे मरने के लिए, कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। यह क्या न्याय है?

दूसरी तरफ, जहां तक नदियों का प्रश्न है यह आश्चर्य की बात है कि जिस बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, दर्जनों नदियां हैं, जिन में साल भर पानी चलता है, गंगा, कोसी, सोन, गंडक, महानन्दा, कनकई, धनार, बागमती ऐसी ऐसी नदियां हैं, इन तमाम नदियां के रहते हुए, और बिहार की जमीन इतनी उर्वरा है, खास कर उत्तरी बिहार में जो भूमि है वह दुनिया की किसी भी उर्वरा भूमि से कम कीमत की और कम उर्वरा नहीं है और वहां पानी है, नदियों में पानी है, भूमि के अन्दर पानी है, लेकिन उस के बावजूद भी बिहार में सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, उस का इन्तजाम नहीं हो पाता है। उत्तरी बिहार के संबंध में मुझे कहना है कि जिस उत्तरी बिहार के ऊपर कहा जाता है कि यह ग्रेनरी है, इस के अन्दर नदियां हैं जिन में बाढ़ आती है, उत्तरी बिहार को उस के 21 हजार वर्गमील क्षेत्रफल में जो वर्षा का पानी आता है उसे तो अपनी छाती पर बहाना पड़ता ही है, इस के अलावा नेपाल के 60 हजार वर्गमील

[श्री लखण लाल कपूर]

क्षेत्र का जो वर्षा का पानी है उस को भी उसे अपनी छाती पर बहाना पड़ता है। इस के बावजूद भी वहां के लिए भारत सरकार की तरह से या बिहार सरकार की तरफ से कोई ऐसी कारगर व्यवस्था नहीं की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वहां जो बाढ़ की विभीषिका है उस की रोकथाम हो सके और जो पानी नदियों में है उस का इस्तेमाल सिंचाई व्यवस्था में हो सके। कोसी की नहर को बनाया गया है, गंडक नहर बन रही है, लेकिन मैं क्या कहूं कोसी की कहानी जिस का काफी भाग सहरसा और पूर्णिया में है, 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की योजना उस से बनाई थी, 1956 से वह योजना चल रही है और आज तक 3 लाख एकड़ जमीन भी पानी पहुंचना नहीं जा सका इस से बढ़ कर विफलता और क्या होगी? बिहार में 86 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है और उत्तर बिहार में 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गरीब मजदूर हैं। ऐसी अवस्था में न तो कृषि की उन्नति वहां हो रही है, न गृह उद्योग की व्यवस्था हो रही है जिस के माध्यम से वहां के बेकार लोगों को काम मिल सके। बिजली के मुताल्लिक भी आज ऐसी हालत है कि बहुत थोड़े से हिस्से में बिजली दे पाये हैं। न पानी है, न बिजली है, न कम्यूनिकेशन के साधन हैं, न सड़क है, यह हाल है हमारे बिहार का। ऐसी स्थिति में हम नहीं समझते हैं हमारे बिहार का क्या हाल होगा?

एक सड़क भारत सरकार ने बनाई है, पार्श्ववर्ती सड़क की योजना बनाई है, बरेली से ले कर अमीनगांव तक और करोड़ों रुपया उस के लिए रखा है। बिहार के अन्दर 411 मील वह सड़क बननी है जिस में 34 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए नियत किया है। 16 करोड़ खर्च हो चुका लेकिन आज तक एक मील भी पक्की सड़क नहीं बनी है। जितनी बंग्लिग इस में हो रही हो उस को कोई देखने वाला नहीं है। सारा रुपया पानी की तरह बहा दिया गया है।

प्रखण्ड विकास कार्यालय धोखे की टट्टी हैं। मैं समझता हूं कि जो करप्शन और जो भ्रष्टाचार का अड्डा जिला और अनुमंडल स्तर पर था, उस करप्शन को विकेन्द्रीकरण कर के इसे गांवों तक पहुंचा दिया गया है। सिवाय भ्रष्टाचार के वहां और कुछ नहीं है, कोई और दूसरा काम नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि बिहार के मामले में भारत सरकार को सोचना चाहिए और इस बजट में कोई नई चीज पेश करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस बजट से बिहार को कोई लाभ होने वाला है।

श्री न० प्र० यादव (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत टकटकी के बाद आप ने समय भी दिया तो सिर्फ 5 ही मिनट। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि कम से कम 5 मिनट और समय बढ़ा दिया जाये: मैं आप का ध्यान बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूं। बिहार में इस तरह की परिस्थिति है कि इस राष्ट्रपति शासन में 1 रुपये बोतल मिट्टी का तेल बिक रहा है। खास कर उत्तरी बिहार में, जहां से मैं आता हूं, आप को सुन कर आश्चर्य होगा की देहात में किसान को मिट्टी का तेल करीब 3 महीने से नहीं मिल रहा है। यदि किसान किसी दूकानदार के पास जाता है तो 1 रुपये 25 पैसे बोतल मिट्टी का तेल वह उसे देता है। यह हालत है। वह गरीब किसान जिन को अभी बिजली देखने को भी कम मिली है उस को एक रुपये सवा रुपये प्रति बोतल मिट्टी का तेल

मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि जो भी इस के अधिकारी हों, शीघ्रातिशीघ्र उचित रेट पर मिट्टी का तेल बिहार के किसानों को मिल सके, इस की व्यवस्था करें। आप को सुन कर आश्चर्य होगा कल एक न्यूज़पेपर में न्यूस आई है, मैं उसे आप के सामने रखना चाहता हूं:

BIHAR TEACHER STARVES TO DEATH

"BIHAR Primary Association Secretary Jagdish Mishra yesterday said a primary teacher Mr. Firoji of the Lower Primary School at Rao block in Gaya district had 'died of starvation' on 10 August. This teacher he added, had not received his salary since April last.

He said most of the primary teachers in the State were 'starving due to non-payment of salaries'.

Demanding a judicial inquiry into this case, he said nearly 65,000 primary school teachers in seven districts—Monghyr, Gaya, Patna, Shahabad, Saran Muzaffarpur and Bhagalpur—had not received their salaries since May last."

श्रीमन, आज बिहार की स्थिति बड़ी दयनीय है। करीब दो साल से 10 हजार इन्जीनियर, गरीब किसानों के लड़के, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ा, लेकिन काम के अभाव में बेकार बैठे हैं। यह बड़े शर्मकी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के जो भी अधिकारी हैं उन से कहना चाहता हूं कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे इन बेकार इन्जीनियरों को जल्द से काम मिल सके। श्रीमन्, इतना ही नहीं बिहार में हज़ारों ग्रेजुएट्स, एम० ए० पास बेकार फिर रहे हैं उन को 100 रु. माहवार की नौकरी भी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिये दर-दर घूमते फिर रहे हैं। आज भी हमारी संसद् के जो सदस्य बिहार के हैं, उन के घरों पर पांच-दस-पन्द्रह इन्जीनियर, ग्रेजुएट्स, एम. ए. पास नौकरी के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार की इस समस्या की तरफ़ जितनी जल्दी हो सके ध्यान देना चाहिये तथा हमारे बिहार के जो भी शिक्षित आदमी बेकार बैठे हैं, उन के लिये नौकरी की व्यवस्था की जाय।

श्रीमन् बिहार की आबादी करीब 5 करोड़ की है, जिसमें कुल 67,665 गांव हैं। अब तक यानी 31 मार्च 1968 तक जिन गांवों को बिजली मिल सकी है, उन की संख्या 5803 है। मैं कुछ दिन पहले मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में गया था, वहां मैंने देखा कि हर तीन-चार एकड़ पर ट्यूब-वेल लगा हुआ है, हर गांव में बिजली की व्यवस्था है। हमारे आदरणीय सिंचाई मंत्री राव साहब दो साल पहले उत्तरी बिहार के दौरे पर गये थे, वहां उत्तरी बिहार की स्थिति को देख कर इन्होंने जनता की भरी सभा में स्वीकार किया था कि 20 मील तक भ्रमण करने के बाद एक भी बिजली का बल्ब इन के देखने में नहीं आया। इन्होंने भरी सभा में कहा था कि यह बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े क्षेत्र में मुझे एक भी बिजली का बल्ब देखने को नहीं मिला। उस समय इन्होंने मुझ से कहा था कि जिस तरह आप सिंचाई सम्मेलन कर रहे हैं, उसी तरह से बहुत जल्दी आप बिजली के लिये भी सम्मेलन कीजिये और यहा तक भी सम्भव होगा—हम भारत सरकार की ओर से आपकी सहायता करेंगे।

बिहार में जहां तक ब्लाक्स की व्यवस्था की बात है—मैं आपका ध्यान बिहार के मुंघेर जिले के अलोली ब्लाक की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां एक किसान किसी का पत्र लेकर अपने काम

[श्री न० प्र० यादव]

के लिये उस ब्लाक में गया। घन्टों प्रखण्ड-विकास पदाधिकारी के दरवाज़े खटखटाता रहा, लेकिन उस का काम नहीं हुआ। जब वह उठ कर खड़ा हुआ और उस ने प्रखण्ड-विकास पदाधिकारी से कहा कि मैं घन्टों से यहां बैठा हुआ हूं—मेरा काम क्यों नहीं होता है—तो आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि उस बेचारे किसान को खींच कर उस प्रखण्ड-विकास पदाधिकारी और उस प्रखण्ड में काम करनेवाले कर्मचारियों ने उस को बुरी तरह से पीटा इस लिये मैं चाहूंगा कि वहां पर शीघ्रातिशीघ्र ज्यूडीशियल इनक्वायरी होनी चाहिये तथा उस प्रखण्ड-विकास पदाधिकारी तथा जो भी उस के सम्बन्धित अधिकारी हैं, उन को सज़ा मिलनी चाहिये।

श्रीमन् मैं उत्तरी बिहार की बाघमती नदी की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। राव साहब उस नदी को देख आये हैं। उन्होंने भरी मीटिंग में कहा था कि इस नदी की मिट्टी में इतनी उर्वरा शक्ति है कि यदि उस की मिट्टी को किसी अन्य प्रदेश में ढो कर ले जाय तो उस से अन्न की काफ़ी उपज होगी। श्रीमन् इस नदी की स्कीम योजना कमीशन के पास महीनों से पड़ी हुई है, मैं चाहूंगा कि योजना कमीशन के पदाधिकारी जितनी जल्दी हो सके, इस की छानबीन कर के उचित कार्यवाही के लिये स्टेट गवर्नमेन्ट को लिखें—यदि इस नदी से नहर बन जाती है तो चम्पारन जिले की, जहां से हमारे श्री विभूति मिश्र आते हैं, 37,760 एकड़ ज़मीन की सिंचाई होगी तथा मुज़फ़रपुर ज़िले की 2 लाख 61 हजार 240 एकड़ ज़मीन की सिंचाई होगी।

इस के बाद मैं अधवारा नदी की योजना की तरफ़ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो कि दरभंगा ज़िला और मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले से हो कर पास करती है। इस अधवारा योजना के लिये 3 वर्ष पहले राव साहब ने एक कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन श्री जाफ़र अली साहब थे। उन्होंने रिपोर्ट दी कि इस योजना पर करीब चार करोड़ रुपये खर्च होंगे और पचास हज़ार एकड़ ज़मीन की सिंचाई होगी, लेकिन अभी तक जाफ़र अली साहब की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि चार करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप इस रकम को दीजिये ताकि यह योजना जल्द से जल्द पूरी हो सके। आपने जो समय दिया है, उस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI K. P. SINGH DEO (Dhenkanal): We are today discussing the Bihar Budget which, ordinarily, we should not have. What is the reason for this ?

In 1967, during the time of the general elections, the level of the administration was at a very low ebb thanks to the Congress misrule of 20 years. In those days, not a single day passed without some charge of corruption being levelled against Congressmen in power in the legislature (*Interruptions*). I am saying what I want to say, not what those interrupting want me to say.

To day we have the Iyer Commission investigating these charges. It is with this background that the UF Government under Shri Mahamaya Prasad Sinha took over. People thought they would have a better government free from corruption, nepotism and favouritism ; they were hoping that they would get a good, clean and just government. But the leaders of the constituents of the UF had time only to quarrel amongst themselves and engage in furthering their interests of their own parties rather than look to the interests of the people or the problems

of the State. They thus threw away the chance which the people had bestowed upon them.

The Congress which had the monopoly of rule for the last twenty years had in Bihar their stronghold and bastion. They had political stability, but they failed to give the people economic and social stability. In disgust, the people voted the Congress out of power. Then came the United Front. The Congress, not bowing to the verdict of the people, found a quisling in Mandal and overthrew the democratic form of government in the State and sneaked into power through the backdoor a minority government propped up by its support.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may continue after the lunch recess.

13.00 HRS.

The Lok Sabha adjourned for lunch till fourteen of the Clock

[*The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five minutes past Fourteen of the Clock*]

(MR. DEPUTY-SPEKAER *in the Chair*)

RE. SITUATION IN CZECHOSLOVAKIA

SHRI SHRI CHAND GOEL (CHANDIGARH) : I have got one little submission. The House was assured that it would be kept constantly informed of the developments in Czechoslovakia. The Minister of Parliamentary Affairs is here. Now, fresh armies have entered Czechoslovakia and firing is being resorted to without even warning the people, who are being subjected to indiscriminate firing. My respectful submission is that the Minister of Parliamentary Affairs must come forward with a statement which we have been assured and which was promised to us so that we would be kept constantly in touch.

श्री शिवचरण लाल (फिरोज़ाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आगरा कलक्टरी पर 71 आदमी भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तोतलपुर में घोर अत्याचार किया गया है। जनता की लाखों रुपए की सम्पत्ति लूट ली गई है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seat.

श्री शिवचरण लाल : हम अपनी बात यहां भी नहीं कहेंगे तो फिर कहां कहेंगे ? क्या इंगलैंड में जाकर कहेंगे ? यह लोक सभा ही हमारी भारत की सभा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please resume your seat. You have had your say.

श्री शिवचरण लाल : हमें न्यायिक जांच का आश्वासन दिलवाया जाए···**

MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing that he says will go on record. The hon. Member should resume his seat. The hon. Member is taking away the time of his party. His party will get less time.

SHRI R. D. BHANDARE (BOMBAY CENTRAL) : You may tell him to raise it in proper form.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Afterwards, the UP budget is coming up and if he wants to raise it then, I shall give him an opportunity at that time.

SHRI SHIV CHARAN LAL :**

SHRI INDER J. MALHOTRA (JAMMU) : Nothing is being recorded. Why should the hon. Member go on like this.

(*Shri Shiv Charan Lal left the House*)

SHRI SHRI CHAND GOEL: Please find out when that statement will be made.

**Not recorded.